

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रक : ९८ / प्र०आ०ता०० / जून--१ / शम्न / २०१४-१५ दिनांक २३/०९/२०१५

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उत्तर नगर नियोजन तथा विलास अधिनियम १८७३ की धारा ३२ के अन्तर्गत दी जा रही है, जिसमें अर्थ यह न समझा जाहिये कि दरा और ग्राम के लालच में जिस गर शम्न मानवित्र एवं कृषि किया जा रहा है, इससे लिखी प्राप्ति या जिसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति उथावा अर्थ के गालिकाना अधिकरों पर किसी का कोई आसर पड़ेगा लभायि यह उत्तमति किसी के निविद्यत या स्वामित्व के शास्त्रिकरों के बेलु नोई प्राप्त न रहेगी।

श्री अमित कुमार गुप्ता य श्री गोदिया गुप्ता द्वारा नजून फ्री होल्ड भुखण्ड सं०-२५ सिविल रेशन, कलाइप रोड, सिविल लाइन्स इलाहाबाद थोन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल शम्न गतिवित्र की स्वीकृति निम्नलिख्य प्रतिवेद्यों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :-

१. उत्तर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १८७३ की धारा १५२ (१) के प्रविधानों के उत्तराधिनियम २००८ में पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपरोक्त अधिनियम लिया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उगाड़ी २००९ में उपरोक्त धारा-२.१.४ एवं ३.१.४ में निर्दिष्ट प्रदिया पूर्ण वर पूर्णता प्रकाशन पत्र प्राप्त करना जापश्यक है।
२. यह स्वीकृती अनांत्रिम (Provisional) स्वीकृति के रूप ये डीपी। निर्माण सूर्ण दोनों के उत्तराधिनियम में आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की जाती पूर्ण करने के पश्चात, निर्माण विशेष दाने वाले 'उत्तराधिनाय-पत्र' प्राप्त करने के बाल ही इस परिसर वा वारादिक लम्योग में जाया जा सकेगा।
३. प्राप्तीकरण द्वारा स्वीकृत मानदेव वरणी। सं० ७३/प्र०आ०ता०००-२/जून-१/२०१४-१५ दिनांक ०६.१२.२०१४ ने अवित्त प्राप्तेवन्दो का उत्तुपालन आनियावर रूप से करना होगा।
४. स्थल वा अधिमोग/उत्तराधिनाय के स्वीकृत प्रस्तवाना के उत्तुपाल छी ही करना होगा।
५. उत्तराधिनाय ने कोई वाद होने अथवा उत्तराधिनाय की स्थिति में प्रदत्त एवं कृष्ण निर्माण नियमों के अधीन होगी, लाभित्र स्थानीय किसी भी दिलाद पर मानवित्र लक्ष्य निरस्त समझा जाएगा।
६. यदि आदेदक द्वारा कोई पठत्वपूर्ण सूचना छिनायी गयी है अथवा गलत जूबना दी गयी है तो उत्तर नगर नियोजन ५० विलास अधिनियम १८७३ धारा १५ (१) के अन्तर्गत मानवित्र निरस्त करने योग्य है।।
७. उत्तर निर्माण से दृढ़ भाली के रास्क को एटरे अथवा सल्लू या नाती के किसी नाम (जो नक्कन के आर भर, पृष्ठ वा अथवा लक्षके आकार के कारण छक गई हो) ले हाति पहुँचे तो युहवाही हैंयार हो जाने ५० १५ दिन के भीतर अथवा यदि विलास प्रक्रियण ने एक लिखित जूबना द्वारा और शीर्ष कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से नरमत कराकर पूर्णता अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण के सन्तोष हो जाए, मैं वर देगा।
८. यह नियमें के लागू इलाज भी ज्यान रखना होना कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९५८ (इण्डियन इलेक्ट्रोस्ट्री लॉल १९८८) नियम ६२ वा उल्लंघन किसी भी घटा में न होना चाहिए। यदि विकास आधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले वाले नहीं तो न ऐसे निर्माण के रोक अथवा उत्तराधिकरण का अधिकारी वा उत्तराधिकरण की जावेंगी।
९. यदि निर्माण ने भास्टर प्लान की उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई एकृति एवं जमड़ी जायेगी और किया गया निर्माण उत्तराधिकरण धोषित कर उत्तर अधिनियम धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही द्वारा प्राप्त गयी जावेंगी।

१२३०९२०१५
(पुष्ट श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
शहरीदार न

